(b) if so, the steps taken in this direction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE): (a) and (b). The Government are constantly considering possibilities of further expansion of bilateral trade with GDR. Periodical trade talks, participation in the Leipzig fair, exchange of business visits and contacts at the level of enterprises and Chambers of Commerce between the two countries, are among some of the steps taken in this direction.

G.D.R. Government's Request for Additional *adhoc* Technical Credit

1068. SHRI KALYANASUNDARAM : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Government of German Democratic Republic has appoached India for the grant of additional *ad hoc* technical credit amounting to Rs. 20 million to enable her to tide over its present balance of payment difficulties with this country ; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (b). Grant of technical credits by the Government of India to other Governments within the frame work of bilateral commercial relationship is of a confidential nature and it would not be in public interest to disclose the details of these arrangements.

रांची में काम कर रहे डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिये जाने के बारे में पुनर्विचार

1069. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री रांची में काम कर रहे डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता की अदायगी के संबंध में 1 अप्रैल, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्गीकृत नगरों में 50 प्रतिशत तक परियोजना भत्ता को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रांची में लगाये गये डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) मौजूदा आदेशों के अन्तर्गत यदि परियोजना किसी वर्गीकृत नगर में स्थित हो तो कोई परियोजना भत्ता नहीं दिया जाता ।

(ख) रांची के डाक-तार कर्मचारी परियोजना भत्ता पाने के पात्र नहीं है ।

(ग) परियोजना भत्ता किसी परियोजना क्षेत्र में काम करने और रहने वाले कर्मचारियों को उस स्थान पर आवास, स्कूल, मार्केट, औषधालयों आदि के अभाव की क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। चूंकि रांची मकान किराया भत्ता देने के लिए वर्गीकृत शहरों के अन्तर्गत आता है और इसमें उपर्युक्त सुख-सुविधाओं का अभाव नहीं है, इसलिए रांची में परियोजना भत्ता देने की यह प्रारम्भिक शर्त पूरी नहीं होती ।

Fall in Prices of Mulbery Cocoon

1070 SHRI S. M. SIDDAYYA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether prices of mulbery cocoons have fallen in Mysore State ;

(b) if so, the reasons for the fall in prices ; and

(c) the steps Government have already taken to stabilise the Prices ?